



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 170]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1984/कार्तिक 26, 1906

No. 170]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1984/KARTIKA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय  
(श्रम विभाग)  
संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1984

सं. भार-11012/1/84-प्राचीन श्रमिक :—पिछले कुछ समय से  
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) में विचार किया जा रहा है  
कि देश में असंगठित श्रम के हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र में नियुक्त  
कामगारों के कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए कौन से संवैधानिक  
और प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। काफी सोच-विचार के पश्चात्  
सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के अधि-  
कारियों, हथकरघा और पावरलूम उद्योग में कामगारों के प्रतिनिधियों और  
नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों का एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल गठित किया  
जाए। त्रिपक्षीय अध्ययन दल का गठन और विचारार्थ विषय निम्नानुसार  
होंगे :—

2 गठन

केन्द्रीय सरकार

1. अपर सचिव,  
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय  
(श्रम विभाग),  
नई दिल्ली।

अध्यक्ष

2. महानिदेशक (श्रम और कल्याण)  
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,  
(श्रम विभाग),  
नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

3. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि  
(कपड़ा विभाग)

सदस्य

4. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य

5. सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

सदस्य

राज्य सरकार :

6. तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

7. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

8. बिहार राज्य सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

9. महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

10. मध्य प्रदेश राज्य सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठन :

11 से 15. केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा  
नामित किए जाने वाले नियोक्ताओं के प्रतिनिधि  
(हथकरघा और पावरलूम उद्योग के उचित  
प्रतिनिधित्व सहित)

5 सदस्य

केन्द्रीय व्यापार संघ संगठन :

16. भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस

सदस्य

17. भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस

सदस्य

18. राष्ट्रीय श्रम संगठन

सदस्य

19. भारतीय मजदूर संघ

सदस्य

20. प्रखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस

सदस्य

## 3. त्रिपक्षीय अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

- (क) उद्योग में श्रमियों के स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया, उद्योग में नियुक्त कामगारों की मजदूरी और कार्य की दशाओं पर विचार करना ;
- (ख) हथकरघा और पावरलूम कामगारों को लागू वर्तमान वैधानिक उपबन्धों और अधिनियमित उपबन्धों के कार्यान्वयन में समय समय पर आई कठिनाइयों का अध्ययन करना; और
- (ग) वैधानिक और प्रशासनिक उपायों पर विचार करना और उनके ध्येय तैयार करना तथा हथकरघा और पावरलूम उद्योग में नियुक्त कामगारों की कार्य की दशाओं में सुधार के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो उत्पादकों पर कर लगा कर कल्याण कोष खोलना ।

## 4. समिति अपनी रिपोर्ट 6 माह के अन्तर प्रस्तुत करेगी ।

लक्ष्मीधर मिश्रा,  
संयुक्त सचिव/महानिदेशक  
(श्रम कल्याण)

## MINISTRY OF LABOUR &amp; REHABILITATION

(Department of Labour)

## RESOLUTION

New Delhi, the 17th November, 1984

**F.No. R-11012/1/84-RW.**—For sometime past the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) has been considering as to what legislative and administrative measures should be taken for improving the working conditions of the workers employed in the handloom and powerloom sector of the Unorganised Labour in the country. After due consideration, it has been decided by the Government to constitute a Tripartite Study Group consisting of the officials of the Central & State Governments Workers' representatives, the Employer's representatives in the Handloom and Powerloom Industry. The composition of the Tripartite Study Group and the terms of reference will be as under :

## 2. COMPOSITION :

## Central Government

- |                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) Additional Secretary,<br>Ministry of Labour & Rehabilitation,<br>(Deptt. of Labour), New Delhi.       | Chairman.             |
| (2) DG(LW) and Joint Secretary,<br>Ministry of Labour & Rehabilitation,<br>(Deptt. of Labour), New Delhi. | Member.<br>Secretary. |
| (3) Representative of the<br>Ministry of Commerce<br>(Department of Textile).                             | Member.               |
| (4) Representative of the<br>Ministry of Home Affairs.                                                    | Member.               |

- (5) Representative of the  
Department of Cooperation. Member.

State Government

- (6) Representative of the  
Govt. of Tamil Nadu Member.

- (7) Representative of the  
Govt. of Uttar Pradesh Member.

- (8) Representative of the  
Govt. of Bihar Member.

- (9) Representative of the  
Govt. of Maharashtra Member.

- (10) Representative of the  
Govt. of Madhya Pradesh. Member.

## Central Employer's Organisations

- (11) to (15) Representatives of employers to 5 Members.  
be nominated by the Central Employer's  
Organisations (with proper representation  
to the handloom and powerloom industry)

## Central Trade Union Organisations :

- (16) Indian National Trade Union Congress Member.  
(17) Indian National Trade Union Congress Member.  
(18) National Labour Organisation Member.  
(19) Bharatiya Mazdoor Sangh Member.  
(20) All India Trade Union Congress Member.

## 3. The terms of reference of the Tripartite Study Group will be as under :

- (a) To consider the nature of recruitment in the Industry the manufacturing process, wages and working conditions of workers employed in the Industry;
- (b) To study the existing legislative provisions which are applicable to the handloom and powerloom workers and the difficulties which may have arisen from time to time in the implementation of the statutory provisions; and
- (c) To consider and formulate the details of legislative and administrative measures including constitution of a Welfare Fund, by levy of cess on the producers as may be considered necessary, for improving the working conditions of the workers employed in the handloom and powerloom industry.

## 4. The Committee will submit its report within six months.

LAKSHMIDHAR MISHRA, Jt. Secy./  
Director General (LW)